

भारत की सांख्यिकी प्रणाली

यह एडिटरियल 12/07/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "[Official Statistical System in India](#)" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की सांख्यिकीय डेटा गुणवत्ता संवीक्षा कार्यप्रणाली और अंतरराष्ट्रीय मानकों की प्रयोज्यता का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है।

प्रलिमिस के लिये:

[सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सातवीं अनुसूची, जनगणना अधिनियम, 1948, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969, सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, तँदुलकर समिति, रंगराजन समिति, आर्थिक जनगणना।](#)

मेन्स के लिये:

भारत की सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

भारत की आधिकारिक सांख्यिकी, विशेष रूप से [राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय \(NSSO\)](#) से प्राप्त आँकड़े या डेटा, की गुणवत्ता के बारे में हाल ही में शुरू हुई बहस ने देश की [सांख्यिकीय प्रणाली](#) से [संबंध महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उजागर](#) किया है। नमूना या सैम्पल डिज़ाइन और डेटा गुणवत्ता के बारे में उठाई गई चर्चाएँ, हालाँकि सांख्यिकीय रूप से वैध साबित नहीं हुई हैं, लेकिन ये भारत के [सांख्यिकीय दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के महत्त्व](#) को रेखांकित करती हैं।

इन बहसों से उजागर होने वाला मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि [भारत के सांख्यिकीय आँकड़े मूलतः त्रुटिपूर्ण](#) हैं, बल्कि यह है कि देश की सांख्यिकीय प्रणाली डेटा वजिज़ान एवं एकीकरण में वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल नहीं रख पाई है।

अपने आधिकारिक आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिये, भारत को अपनी [सांख्यिकीय कार्यप्रणाली \(statistical methodologies\)](#) को [आधुनिक बनाने](#), डेटा जारी करने की [आवृत्त एवं समयबद्धता में सुधार करने](#) और [डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण](#) के लिये अभिनव दृष्टिकोणों की खोज करने में नविश करने की आवश्यकता है। यह नीति निर्माताओं को तेज़ी से बदलते [आर्थिक एवं सामाजिक परदृश्य में सूचना-संपन्न नरिण्य लेने के लिये आवश्यक सटीक एवं अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण](#) होगा।

भारत में वर्तमान सांख्यिकीय ढाँचा क्या है?

■ केंद्र सरकार:

- [सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय \(MoSPI\)](#) देश की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
 - MoSPI के अंतर्गत कार्यरत [राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय \(NSO\)](#) [राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली](#) के एकीकृत विकास की नगिरानी करता है।
 - NSO में [केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय \(CSO\)](#) और [राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय \(NSSO\)](#) शामिल हैं।
 - NSO के अलावा, विभिन्न संबंधित [मंत्रालय/वभाग डेटा संग्रहण, प्रसारण और समन्वयन](#) के लिये NSO के साथ अपने सांख्यिकीय प्रतिष्ठान का संचालन करते हैं।

■ राज्य सरकार:

- राज्यों में आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली आमतौर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच वकेंद्रीकृत होती है।
 - शीर्ष स्तर पर [आर्थिक एवं सांख्यिकी नदिशालय \(Directorates of Economics & Statistics- DES डीईएस\)](#) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करते हैं।
 - अधिकांश क्षेत्रों के लिये डेटा [संग्रहण, संकलन, प्रसंस्करण और परिणाम](#) तैयार करने की ज़िम्मेदारी राज्यों की है तथा राज्यवार आँकड़े केंद्र द्वारा उपयोग किये जाने वाले राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों में योगदान देते हैं।

■ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC):

- [सी. रंगराजन आयोग](#) की सफ़ारिशों के आधार पर वर्ष 2006 में स्थापित NSC सांख्यिकीय मामलों पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप

में कार्य करता है।

■ **सातवीं अनुसूची में शामिल:**

- 'सांख्यिकी' विषय को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ और समवर्ती दोनों सूचियों में शामिल किया गया है, जिसे विशेष रूप से **परवर्ष 94 (संघ सूची) और परवर्ष 45 (समवर्ती सूची)** के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

■ **वधायी ढाँचा:**

- सांख्यिकी को नियंत्रित करने वाले वशिष्ट वधायी अधिनियमों में **जनगणना अधिनियम, 1948; जनम और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969;** और **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008** शामिल हैं।

भारत की सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **जनगणना में देरी और इसके नहितारथ:** भारत की वर्ष 2021 की जनगणना को बार-बार स्थगित किया जाना देश की सांख्यिकीय प्रणाली में एक गंभीर व्यवधान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका शासन, नीति-निर्माण और संसाधन आवंटन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं:

- **नीति विकृतियाँ:** पुराने पड़ चुके **जनसांख्यिकीय आँकड़े** के कारण असंगत नीतियों का निर्माण होता है।
 - उदाहरण के लिये, स्कूल अवसंरचना और शिक्षक भर्ती के लिये शिक्षा संबंधी योजना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आँकड़ों पर आधारित है, जो तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों की वर्तमान आवश्यकताओं को संभावित रूप से कम करके आँकती है।
- **त्रुटिपूर्ण आर्थिक गणना:** इस देरी से राज्यवार गरीबी अनुपात और केंद्र-राज्य कर बँटवारे के संशोधन पर असर पड़ता है।
 - संभव है कि बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों, जिनकी **जनसंख्या वृद्धि दर अधिक** है, को एक दशक पुराने आँकड़ों के आधार पर अपर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त हो रहा है।

- **GDP आकलन कार्यप्रणाली से जुड़ी चर्चाएँ:** भारत की GDP आकलन वधियों को संभावित अति-आकलन के लिये संवीक्षा का सामना करना पड़ा है, जिससे आर्थिक विकास के आँकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिये, **भारत की GDP सीरीज़ के वर्ष 2015 के संशोधन** ने गंभीर विवाद को जन्म दिया।

- इसने **वर्ष 2013-14 के लिये सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 4.7%** से बढ़ाकर **6.9%** कर दिया, जिससे इसकी सटीकता पर संदेह पैदा हुआ।
- पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार **अरवि सुब्रमण्यन** ने मत दिया कि **वर्ष 2015 में जारी 2011-12 GDP सीरीज़ में वृद्धि का अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर** लगाया गया है। इससे भारत **वर्ष 2015 में चीन को पीछे छोड़कर** सबसे तेज़ी से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया।

- **रोज़गार संबंधी आँकड़ों की विश्वसनीयता और आवृत्ति:** NSSO के व्यापक रोजगार-बेरोज़गारी सर्वेक्षणों को बंद करने से आँकड़ों में महत्वपूर्ण अंतराल पैदा हो गया।

- वर्ष 2017-18 में शुरू किये गए **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** को कार्यप्रणाली संबंधी परिवर्तनों (जिससे पछिले सर्वेक्षणों के साथ तुलना करना कठिन हो गया) के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा।
- यह मुद्दा सुसंगत, तुलनीय और बारंबार श्रम बाज़ार आँकड़े की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- **गरीबी आकलन संबंधी चुनौतियाँ:** सरकार ने वर्ष 2011-12 के बाद से गरीबी का आधिकारिक अनुमान जारी नहीं किया है, जिसका आंशिक कारण कार्यप्रणाली को लेकर जारी बहस है।

- **तुंदलकर समिति** की कार्यप्रणाली—जिसने वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गरीबी रेखा को 27 रुपए प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिये **33 रुपए** प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित किया था—की आलोचना की गई कि इसने आधार को अत्यंत नमिन रखा है।
 - रंगराजन समिति ने उच्चतर सीमा का सुझाव दिया था, लेकिन इसकी सफ़ािशों को आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया।
- आम सहमति और **अद्यतन आँकड़ों के अभाव के कारण गरीबी के अनौपचारिक अनुमानों में व्यापक भिन्नताएँ** सामने आई हैं, जिससे प्रभावी नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई है।

- **कोविड-19 के दौरान मृत्यु दर के आँकड़ों में विसंगतियाँ:** कोविड महामारी ने भारत की मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में गंभीर अंतराल को उजागर किया।

- **वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, वर्ष 2020 और 2021 में भारत में कोविड-19 के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 4.7 मिलियन मौतें होने की संभावना है।

- भारत ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2021 तक **कोविड-19 से जुड़ी केवल 4.8 लाख संघीय मौतों** का अनुमान लगाया, जिसका अर्थ है कि WHO का अनुमान सरकारी गणना से लगभग 10 गुना अधिक है।

- यह भारी विसंगत मृत्यु पंजीकरण और मृत्यु-कारण (**cause-of-death**) रपिपोर्टिंग के बारे में संदेह पैदा करती है, जबकि स्वास्थ्य नीति और जनसांख्यिकीय अनुमानों के लिये इनकी सही रपिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है।

- **अनौपचारिक क्षेत्र मापन से संबद्ध चुनौतियाँ:** भारत का वशिाल अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमें अनुमानतः **80% से अधिक कार्यबल कार्यरत** है, मापन संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

- **आर्थिक जनगणना (6टी) के आँकड़े पछिली** बार वर्ष 2013-14 में जारी किये गए थे और 7वीं आर्थिक जनगणना के आँकड़े अभी तक जारी नहीं किये गए हैं।

- छठी आर्थिक जनगणना में **58.5 मिलियन प्रतिष्ठानों** की रपिपोर्टिंग की गई थी, लेकिन वशिषज्जों का तर्क है कि इसमें संभवतः गृह-आधारित और अत्यधिक गतिशील आर्थिक गतिविधियों की गणना कम की गई है।

- इस क्षेत्र के बारे में ठोस आँकड़ों का अभाव अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिये नीति निर्माण को प्रभावित करता है।

- आँकड़ों को दबाना और वलिंबित प्रकाशन: प्रतिकूल सांख्यिकीय रपिपोर्टों को रोके रखने के कई उदाहरण सामने आए हैं।

- इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण NSSO का वर्ष 2017-18 का उपभोग व्यय सर्वेक्षण (**consumption expenditure survey**) है, जिसमें कथित तौर पर ग्रामीण उपभोग में गतिवट देखी गई।

- इस सर्वेक्षण को डेटा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए जारी होने से रोका दिया गया। इस तरह की कार्रवाईयें सांख्यिकीय संस्थानों

की स्वतंत्रता और सांख्यिकीय प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाती हैं।

- **प्रौद्योगिकीय एकीकरण और बगि डेटा के उपयोग का अभाव:** 'डजिटल इंडिया' जैसी पहलों के बावजूद, आधिकारिक आँकड़ों में बगि डेटा और उन्नत विश्लेषण का एकीकरण सीमिति बना हुआ है।
 - उदाहरण के लिये, जबकि **एसटोनिया जैसे देश रयिल-टाइम आर्थिक संकेतकों** के लिये डजिटल फुटप्रिंट का उपयोग कर रहे हैं, भारत की सांख्यिकीय प्रणाली अभी भी पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों पर अत्यधिक निर्भर करती है।
 - आर्थिक और कृषि सांख्यिकी को उन्नत बनाने के लिये **GST डेटा और डजिटल लेनदेन** की क्षमता का अभी तक बड़े पैमाने पर दोहन नहीं हुआ है।
- **पर्यावरण संबंधी आँकड़ों का अभाव:** भारत में व्यापक एवं नयिमिति रूप से **अद्यतन किये जाते पर्यावरण संबंधी आँकड़ों** का अभाव पाया जाता है।
 - उदाहरण के लिये, देश में अंतिम व्यापक वन सर्वेक्षण, जिसमें भू-सत्यापन का उपयोग किया गया था, 1980 के दशक में किया गया था और उसके बाद के सर्वेक्षण मुख्यतः उपग्रह डेटा पर निर्भर बने रहे।
 - इससे जलवायु नीति और अंतरराष्ट्रीय प्रतबिद्धताओं के लिये महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र अनुमान और कार्बन पृथक्करण गणना की परिशुद्धता प्रभावित होती है।

भारत में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **व्यापक कानूनी और संस्थागत सुधार:** पुराने सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2017 में संशोधित) के स्थान पर एक नया सांख्यिकी अधिनियम लागू किया जाए।
 - विधायी सुधारों के माध्यम से **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जैसी सांख्यिकीय एजेंसियों की स्वायत्तता को सशक्त** किया जाए, जहाँ यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके पास राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना आँकड़े जारी करने का अधिकार हो।
 - सभी सरकारी विभागों में **सांख्यिकीविदों की भरती और करियर** प्रगति को सुचारू बनाने के लिये राष्ट्रीय सांख्यिकी सेवा को सुव्यवस्थिति किया जाए।
 - सरकार के सभी आधिकारिक सांख्यिकीय उत्पादों में डेटा की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली मानकों की निगरानी के लिये एक स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना की जाए।
- **डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण अवसंरचना का आधुनिकीकरण:** कागज़-आधारित सर्वेक्षणों के स्थान पर **टैबलेट या स्मार्टफोन-आधारित डेटा प्रविष्टि** के साथ एक राष्ट्रव्यापी डजिटल डेटा संग्रहण प्रणाली को लागू किया जाए।
 - सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ एक केंद्रीकृत, क्लाउड-आधारित डेटा भंडारण और प्रसंस्करण अवसंरचना का विकास किया जाए।
 - अधिक व्यापक और बारंबार डेटा अपडेट के लिये विभिन्न प्रशासनिक डेटाबेस (जैसे GST, आयकर, भूमि रिकॉर्ड) को सांख्यिकीय प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए।
 - समयबद्ध आर्थिक निगरानी के लिये प्रमुख आर्थिक संकेतकों (जैसे बजिली की खपत, ई-वे बलि जैसे उच्च आवृत्ति संकेतक) से रयिल-टाइम डेटा पाइपलाइनों की स्थापना की जाए।
- **क्षमता निर्माण और कौशल संवर्द्धन:** सभी स्तरों पर सरकारी **सांख्यिकीविदों के नरिंतर कौशल उन्नयन** के लिये एक समर्पित सांख्यिकी प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया जाए।
 - ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम अभ्यास के अंगीकरण के लिये अग्रणी वैश्विक सांख्यिकीय संगठनों और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी विकसित की जाए।
- नीति-निर्माण में संलग्न सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों के लिये अनिवार्य सांख्यिकीय साक्षरता कार्यक्रम लागू करें।
- **उन्नत डेटा पारदर्शिता और अभिगम्यता:** मेटाडेटा और कार्यप्रणाली सहित सभी आधिकारिक आँकड़ों तक पहुँच प्रदान करने के लिये एक उपयोगकर्ता-अनुकूल राष्ट्रीय डेटा पोर्टल विकसित किया जाए।
 - पूर्वानुमान सुनिश्चित करने और अटकलों को कम करने के लिये सभी प्रमुख सांख्यिकीय वजिप्तियों के लिये पूर्व-घोषित कैलेंडर लागू करें।
 - प्रमुख सांख्यिकीय उत्पादों में प्रमुख कार्यप्रणाली संबंधी परिवर्तनों के लिये सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया स्थापित की जाए।
- **उप-राष्ट्रीय सांख्यिकीय क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना:** राज्य स्तरीय सांख्यिकीय प्रणालियों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये **राज्य सांख्यिकीय नवाचार नधि (State Statistical Innovation Funds)** का निर्माण किया जाए।
 - स्वस्थ प्रतसिपर्द्धा और सुधार को बढ़ावा देने हेतु राज्य सांख्यिकीय क्षमताओं के लिये एक रैकगि प्रणाली लागू किया जाए।
 - छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता के लिये क्षेत्रीय डेटा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किये जाएँ।
- **ब्लॉकचेन और डिसट्रीब्यूटेड लेजर (Distributed Ledger) प्रौद्योगिकी:** आधिकारिक आँकड़ों में सभी परिवर्तनों का अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल बनाए रखने के लिये ब्लॉकचेन को लागू किया जाए।
 - विभिन्न सरकारी विभागों के **बीच स्वचालित डेटा साझाकरण समझौतों** के लिये स्मार्ट अनुबंधों का उपयोग करें।
 - सुरक्षा एवं पारदर्शी **घरेलू सर्वेक्षण के लिये एक ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली** का सृजन किये जाए, ताकि संग्रहण से प्रकाशन तक आँकड़ों की अखंडता सुनिश्चित हो सके।
- **बगि डेटा एनालिटिक्स और वैकल्पिक डेटा स्रोत:** बड़े डेटा स्रोतों (जैसे मोबाइल फोन गैर-व्यक्तिगत डेटा, सोशल मीडिया, वेब स्क्रैपिंग) को आधिकारिक आँकड़ों में शामिल करने के लिये कार्यप्रणालियों विकसित की जाएँ।
- **जनगणना और नमूना सर्वेक्षण प्रणालियों में सुधार लाना:** एक रोलगि जनगणना मॉडल को लागू किया जाए, जहाँ एकल दशकीय अभ्यास के बजाय **5 वर्ष की अवधि में लगातार सर्वेक्षण** आयोजित किये जाएँ।
 - सभी घरेलू सर्वेक्षणों के लिये वार्षिक रूप से अद्यतन किये जाने वाला मास्टर सैम्पल फ्रेम विकसित किया जाए।
 - ऐसे अनुकूली सर्वेक्षण डिज़ाइन प्रस्तुत किये जाएँ जो **रयिल-टाइम डेटा गुणवत्ता संकेतकों** के आधार पर नमूना आकार को समायोजित करते हों।

अभ्यास प्रश्न: गरीबी और रोज़गार जैसे प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के परिशुद्ध मापन में भारत की सांख्यिकीय प्रणाली के समक्ष वदियमान

चुनौतियों की चर्चा कीजिये। भारत के सांख्यिकीय आँकड़ों की साख एवं वश्वसनीयता को बढाने के लयि कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2009)

1. भारत की जनसंख्या का घनत्व वर्ष 1951 की जनगणना और वर्ष 2001 की जनगणना के बीच तीन गुना से अधिकि बढ गया है।
2. भारत की जनसंख्या की वार्षकि वृद्धिदर (घातीय) वर्ष 1951 की जनगणना और वर्ष 2001 की जनगणना के बीच दोगुनी हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/strengthening-india-s-statistical-system>

